**E-ISSN:** 2664-603X
**P-ISSN:** 2664-6021
IJPSG 2025; 7(8): 01-03
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 02-05-2025
Accepted: 06-06-2025

**डॉ. बीना जोशी**
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, इन्दिरा प्रियदर्शिनी राज. महिला स्नातकोत्तर वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल भारत

**Corresponding Author:**
**डॉ. बीना जोशी**
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, इन्दिरा प्रियदर्शिनी राज. महिला स्नातकोत्तर वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल भारत

# उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन पैटर्न पर बेरोजगारी के प्रभाव का अध्ययन (उत्तराखण्ड के जिला अल्मोड़ा के एक गाँव बधाण पर केन्द्रित) पर्यवेक्षणात्मक एवं अनुभववादी अध्ययन

**बीना जोशी**

**DOI:** https://doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i8a.610

**सारांश**
हिमालय की मिट्टी और जल पूरे देश के काम आता हैं। हिमालय ऑक्सीजन का भण्डार है तथा जलवायु को नियन्त्रित करता है। उपभोक्तावादी अविवेकपूर्ण विकासवादी दृष्टि कभी हिमालय में टिकाऊ विकास नहीं कर सकी। पहाड़ के गाँव शहर की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। जंगल, पानी एवं मिट्टी होने के बावजूद भी पहाड़ को विकास से वंचित रखना असमानता है। शहर के समाज ने सब सब कुछ भोगा किन्तु पहाड़ के गाँव इससे वंचित रहे। शहर के पास सब कुछ है और गाँव उससे वंचित है तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था का चरमरा जाना तय है। परिणामस्वरूप पहाड़ से मैदान की तरफ ही पलायन नहीं हो रहा बल्कि पहाड़ के गाँव पहाड़ के शहर की तरफ भी पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी पलायन का सबसे बड़ा कारण है। पलायन के कारण, प्रभाव एवं समाधान प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य है।

**कुटशब्दः** बधाण (जिला अल्मोड़ा का एक गाँव), राजनीतिक विकास एवं जागरूकता, Apples (स्विस गाँव), जूरा पर्वत (यूरोप), बुरांश (फूल), किलमोड़ी (जंगली पौधा), सम्यो (प्राकृतिक धूप वाला पौधा), तिमूर (प्राकृतिक दातुन), जुरान तकनीक (इजरायल)

## प्रस्तावना
उत्तराखण्ड की अवधारणा के पीछे यहाँ की दुर्गम परिस्थितियाँ एवं संवेदनशील हिमालय की चिन्ता छिपी है। पिछले 20 वर्षों में 4,000 से अधिक गाँव खाली हो चुके हैं। कुछ गाँव बंजर होना शुरू हो गए हैं जहाँ गिने–चुने बुजुर्ग ही रहते हैं। खाली होते गाँव सरकार को डरा नहीं पा रहे हैं। पहाड़ पर डॉक्टर व अध्यापक जाने को तैयार नहीं हैं। 2023 तक 1792 गाँव भुतहा हो चुके हैं, 4 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं। अल्मोड़ा एवं पौड़ी जैसे जिले भी जल्द ही बंजर होने के कगार पर हैं। उत्तराखण्ड की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी राज्य छोड़ चुकी है। उत्तराखण्ड बनने के बाद 32 लाख से अधिक लोगों ने पहाड़ छोड़ दिया है। अब वक्त आ गया है कि इसे रोका जाय अन्यथा इस समस्या से निपटना मुश्किल हो जाएगा। हम रोजगार बढ़ाकर पलायन को काफी हद तक रोक सकते हैं।

## समस्या के कारण
### राजनीतिक विकास की लौ से दूर हैं गाँव
पलायन के पीछे मुख्य कारण बेरोजगारी तो है लेकिन इस कारण को मजबूत करने के पीछे भी अनेक कारण हैं जैसे–असुविधा, भूगोल, चढ़ाई, यातायात के साधनों का अभाव, अशिक्षा, तकनीक, प्रौद्योगिकी व उद्यम का अभाव, सर पर सामान ढोना, महिलाओं का शहर की चकाचौंध भरी जिन्दगी की ओर रूझान, शारीरिक कार्य न करने की परम्परा का उदय, वैज्ञानिक सोच का अभाव, प्राकृतिक संसाधनां का सही इस्तेमाल न होना, राजनीतिक विकास का अभाव, कृषि का आधुनिकीकरण न होना, विशिष्ट कृषि परम्परा का उदय न होना, पहाड़वासियों की पहाड़ में न रहने की सोच का विकसित होना, डेनमार्क की तर्ज पर डेयरी उद्योग का विकास न होना, सस्ते राशन के कारण अकर्मण्यता का उदय इत्यादि।

### पलायित परिवार भी जिम्मेदार
पलायित परिवार वर्षों में एक बार पूजा के लिए आता है और एक रात रहकर शहर लौट जाते हैं। अच्छे रोजगार में होने के बाद भी पहाड़ में निवेश की नहीं सोचता।

परिणामस्वरूप अन्य परिवार भी गाँव छोड़कर मैदान में बसने की सोचते हैं। यह मानसिकता पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रान्सफर हो रही है जिससे पलायन का चक्र बढ़ता चला जाता है।

### पहाड़ की वस्तु की पहाड़ में कीमत क्यों नहीं होती?

शहर में आते ही उस वस्तु की कीमत 100 गुना बढ़ जाती है। विपणन व्यवस्था की सही नीति न होने के कारण पहाड़ी फल एवं सब्जियाँ खेतों में सड़ते हैं जबकि भारत में वहीं सूखी खुबानी विदेशों से 100 रूपया प्रति पैकेट की दर से मँगायी जाती है। सरकार को ड्राईफ्रूट की तकनीक सिखाकर गाँव में ही उद्यम स्थापित करना चाहिए।

### महिलाएँ भी जिम्मेदार

पहाड़ की पढ़ी–लिखी महिलाएँ पहाड़ के गाँवों में ससुराल नहीं चाहती जिससे गाँवों की व्यवस्था टूटी है।

### उद्यम का अभाव

गाँव के लोग राजनीतिक विकास व जागरूकता के अभाव के कारण अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं जिस कारण सरकार सही नीहत नहीं बनाती परिणामस्वरूप वे आर्थिक लाभ नहीं उठा पाते।

### गाँव के प्रति सरकार की मनोवृत्ति

स्रकार पलायन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। ठोस नीति के अभाव के कारण सस्ता अनाज व दालें देकर सरकार उन्हें गरीब बनाती गई परिणमस्वरूप वे कभी उद्यमी नहीं बन पाए और इस प्रकार वे मैदानी लोगों से प्रतिस्पर्धा करने में असफल रहे। आधुनिक तकनीक से पहाड़ के गाँव आज भी अछूते हैं। नेताओं का गाँव से कोई भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध नही है। उत्तराखण्ड के राजनीतिक नेतृत्व ने नौकरशाही को नकारात्मक रूप से बढ़ावा दिया है। मैदानी भागों में सिमटी राज्य सरकार बँजर होते पर्वतीय गाँवों के विकास के लिए कोई कार्य नहीं कर पा रही है।

### परिकल्पना व समाधान (पलायन की चुनौती बधाड़ गाँव के सन्दर्भ में)

उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा जिले के अन्तर्गत रानीखेत शहर से मात्र 5 किमी0 की दूरी पर गाँव है जो सभी प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर होते हुए भी यह गाँव 40 साल के अन्दर तेजी से खाली हुआ है। उदासीनता एवं अकेलापन के साथ गाँव भविष्य की भयावह तस्वीर पेश करते हैं।

40 वर्ष पूर्व गाँव के परिवारों की स्थिति

| वर्ष | परिवार | जनसंख्या | व्यवसाय | नौकरी |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 40 | 210 | कृषि, दुग्ध | 16 |

1985 तक कृषि से परिवार का भरण–पोषण हो जाता था, फलों से पेड़ लदे रहते थे लेकिन आज बँजर धरती है।

| वर्ष | परिवार | जनसंख्या | व्यवसाय | नौकरी |
|---|---|---|---|---|
| 1925 | 20 | 60 | कृषि, मजदूरी | 02 |

तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि गाँववासी कृषि के स्थान पर मजदूरी करना पसन्द कर रहे हैं। गाँव के 10 घर ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक या दो बुजुर्ग रह गए हैं। ये परिवार भी धीरे–धीरे खाली हो जाएंगे। 10 परिवारों के बुजुर्ग एकाकीपन का जीवन जी रहे हैं। अगर सरकार चाहती तो छोटे उद्योग खोलकर गाँव में ही रोजगार दे सकती थी पर ऐसा हुआ नही। ग्राम प्रधान के पद पर 40 सालों से एक ही परिवार का कब्जा है। वंशवादी परम्परा को तोडकर निर्णय निर्माण में गाँव की सहभागिता बढ़ानी चाहिए।

### बघाड़ गाँव के पलायन की स्विस Apples गाँव से तुलना

यदि पहाड़ के गाँवों से पलायन रोकना है तो रोजगार के लिए स्विस मॉडल को अपना सकते हैं।

वर्ष 2025 (बघाड़ गाँव)

| राज्य | जिला | गाँव | परिवार | पलायित परिवार | व्यवसाय | राजनीतिक हल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तराखण्ड | अल्मोड़ा | बघाड़ | 20 | 150 | कृषि | 0 |

वर्ष 2025 (स्विस गाँव)

| वर्ष | देश | केन्टन | जिला | गाँव | परिवार | ज्नसंख्या | राजनीतिक दल | व्यवसाय | पलायन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | स्विटजरलैण्ड | Vaud | Morges | Apples | 223 | 1306 | Green Party, Green Liberal Party | Sports Nursing Riding School | शहर से गाँव की ओर पलायन |

स्विटजरलैण्ड के Apples गाँव का भूगोल उत्तराखण्ड के बधाड गाँव से भी मुश्किल भरा है। आल्पस व जूरा पर्वतों से घिरा गाँव बँजर है। आधुनिक तकनीक व राजनीतिक विकास के कारण यह गाँव काफी विकसित एवं पलायन शून्य है। Wood carring, Lace making, Embroidery, दुग्ध, सूक्ष्म यन्त्र उद्योग विकसित हैं।

### स्विस गाँव की तर्ज पर बघाड़ गाँव का राजनीतिक व आर्थिक विकास कैसे हो?

सर्वप्रथम गाँव में रहने वालों की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा ताकि शहरों में रहने वाले गाँव के लोग गाँव की ताजी हवा की ओर जाने को कदम बढ़ाएँ। प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर इन्टरनेट की सुविधा देकर सरकार बाँस की खेती, शहतूत बागवानी, मौन पालन, गुलाब की खेती, तुलसी उत्पादन, किलमोड़ी जड़, मिनरल वाटर, आँवला, स्यूता, अखरोट इत्यादि उद्यम से जोड़कर विपणन की व्यवस्था उत्पाद हेतु सरकार करे। सरकार गाँवों का ग्रुप बनाकर दुग्ध डेयरी, उपला पैकिंग, खाद पैकिंग, गोमूत्र शोध, अखरोट पैकिंग, तुलसी, पुदीना, गुलाब अर्क, खुबानी, पुलम, चुंगारू का ड्राईफ्रूट, गिलमोड़ी की जड़ से मधुमेह की दवा, बुरांश के फूल से स्क्वेंस, भाँग के पौधे से कैरी बैग, शहद पैकिंग, आटा पीसने के पुराने घराट को पुनर्जीवित करना आदि आर्थिक उत्पाद तैयार कर मार्केटिंग में गाँव का साथ दे सकती है। यदि गाँव का आर्थिक विकास होगा तो गाँववासी पलायन नहीं करेंगे। सम्यो से धूप, तिमूर से पेस्ट, रीठा से शैम्पू की भी अपार संभावनाएँ हैं। जब गाँव हरा–भरा, फल–फूलों से लदा होगा तो स्वाभाविक है कि पलायित परिवार वापस आएँगे। एग्रो फारेस्ट, पर्यटन, गायों के नस्ल सुधार इत्यादि क्षेत्रों में इजरायल की जुरान तकनीक का प्रयोग करें।

## निष्कर्ष

गाँव के प्रति शहरी लोगों की मनोस्थिति में परिवर्तन लाना, राजनीतिक व आर्थिक विकास, डत्पादों को बाजार डपलब्ध कराना, निर्णय निर्माण में भागीदारी, गाँव के प्रति अन्याय का प्रतिकार करना इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। सरकार द्वारा गाँव में ही रोजगार की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए तभी पलायन की समस्या का स्थायी समाधान होगा। जैसे शहरों के लिए नीतियाँ बनती हैं वैसे ही गाँवों के लिए भी नीतियों का निर्माण होना चाहिए। पहाड़ का नेता चुनावों में पहाड़ों का उम्मीदवार होते हैं किन्तु जीतने के बाद मैदान में बड़े कारोबार का मालिक बन जाता है। ऐसे लोगों से गाँव की जनता को सावधान रहना है। सरकार द्वारा गाँवों के प्रति कोई सरोकार न होने के कारण शराब व भू–माफिया हावी होने हैं। इस प्रकार के असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है।

## सन्दर्भ


1. New Aspects of Political Development, Lucian Pye
2. Related Researches Swiss Migration Villages Review
3. Hans HuberBook, How Switzerland Governed
4. ग्राम सभा बघाड़, Documents
5. Unemployment, Migration and Livelihood in the Hill Economy of Uttarakhand, Rajendra P. Mamgain (2004)
6. Himalayan out Migration, R.S. Bora (1996)
7. गाँव बचाओ आन्दोलन, सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रकाश जोशी
8. जुरान तकनीक, Alzazeera.com
9. Stages of Political Development, Organsky
10. Beyee, Modern Documents
11. उत्तराखण्ड क्यों नहीं बना हिमाचल, रामचन्द्र गुहा का आलेख नवम्बर 2015
12. प्रकृति सियासत नहीं करती, Lob Freedman